

जनहति प्रतिक्रिया दावा कार्यवाही

प्रलिस के लिये:

सीलबंद कवर कार्यवाही, जनहति प्रतिक्रिया दावा कार्यवाही।

मेन्स के लिये:

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने न्यायालयों में [सीलबंद कवर कार्यवाही](#) के उपयोग और एक मलयालम चैनल के प्रसारण प्रतबंध मामले पर नरिणय सुनाया।

- न्यायालय ने मीडिया में आवाज़ों को दबाने एवं [संवैधानिक अधिकारों](#) को कम करने तथा नषिपक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक गारंटी हेतु सरकार की आलोचना की।
- न्यायालय ने [सीलबंद कवर \(मोहरबंद लफिफा\)](#) के उपयोग को बदलने हेतु [जनहति प्रतिक्रिया दावा कार्यवाही](#) के लिये एक वैकल्पिक प्रक्रिया भी तैयार की।

सीलबंद कवर कार्यवाही:

- [सीलबंद कवर कार्यवाही](#) का उपयोग अक्सर [संवेदनशील या गोपनीय जानकारी](#) जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों या ऐसे मामलों में किया जाता है जहाँ साक्ष्यों के प्रकटीकरण में [शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता](#) से समझौता हो सकता है।
- ऐसे मामलों में दस्तावेज़ या साक्ष्य न्यायालय में सीलबंद लफिफे में प्रस्तुत किये जाते हैं और केवल न्यायाधीश एवं एक नामित न्यायिक अधिकारी को [सीलबंद लफिफे की सामग्री की जाँच करने की अनुमति](#) होती है।
 - मामले के पक्षकारों की सीलबंद कवर की सामग्री तक पहुँच नहीं होती है और न्यायालय अपने नरिणयन हेतु केवल सीलबंद कवर में नहिति जानकारी पर भरोसा करते हैं।
- सीलबंद कवर कार्यवाही [संवेदनशील जानकारी या व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करने के साथ](#) [न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता](#) की आवश्यकता को संतुलित करने का एक साधन है।
 - हालाँकि, [सीलबंद कवर के उपयोग ने संवैधानिक अधिकारों](#) एवं कानून के तहत नषिपक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक गारंटी को कम कर दिया है।

जनहति प्रतिक्रिया दावा कार्यवाही:

- **परिचय:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के लिये राज्य के दावों से नपिटने के दौरान [सीलबंद कवर कार्यवाही](#) हेतु "वकिल्प" के रूप में "कम प्रतबंधात्मक" जनहति प्रतिक्रिया (PII) दावा कार्यवाही को वकिसति किया।
 - PII की कार्यवाही एक "गुप्त बैठक" होगी, लेकिन राज्य के PII के दावे को अनुमति देने या खारज़ि करने का एक तर्कपूर्ण आदेश खुले न्यायालय में घोषित करने का प्रावधान है।
- **प्रक्रिया - न्यायमतिर (एमकिस क्यूरी) की भूमिका:**
 - न्यायालय द्वारा न्यायमतिर (एमकिस क्यूरी), जिसका अर्थ "न्यायालय का मतिर" है, की नियुक्ति की जाएगी, जो जनहति प्रतिक्रिया दावों में शामिल पक्षों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा।
 - न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमतिर को राज्य द्वारा रोके जाने की माँग की गई है, जिसके लिये उन्हें दस्तावेज़ों को

प्रदान किया जाएगा और कार्यवाही से पूर्व आवेदक तथा उनके अधिवक्ता के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनके मामले का पता लगाया जा सके।

- जनहित प्रतिकक्षा कार्यवाही शुरू होने के पश्चात् न्यायमन्त्रि, आवेदक या उनके अधिवक्ता के साथ बातचीत नहीं करेगा जिसके लिये अधिवक्ताओं ने दस्तावेज़ को रोके जाने की माँग की है।
- न्यायमन्त्रि "अपनी कषमता के अनुसार आवेदक के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा" और किसी अन्य व्यक्तिके साथ दस्तावेज़ पर चर्चा नहीं करने की शपथ से बाध्य होगा।

■ त्रुटियाँ/दोष :

- चूँकि **संवधान का अनुच्छेद 145** विशेष रूप से अनविरय करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी नरिणय स्वतंत्र रूप से दिये जाएं, PII के अनुसार गुप्त बैठक की कार्यवाही इस संवधानिक आदेश के वरिद्ध हो सकती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया: जबकि न्यायालय ने यह माना कि जनहित प्रतिकक्षा कार्यवाही एक गुप्त बैठक में होगी, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय को स्वतंत्र रूप से नरिणय देने या खारज़ि करने के लिये एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त सीलबंद कवर कार्यवाही न्याय के प्राकृतिक मानदंडों के साथ-साथ पारदर्शी व प्रत्यक्ष न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तथा PII के दावों का भी न्याय के इन मानकों पर प्रभाव पड़ता है।

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय अन्य टपिपणियाँ:

■ पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य मामला (2019):

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही जाँच जारी हो तथा दस्तावेज़ों से नई जानकारी मलि सकती हो, अभियुक्तों के लिये इसका प्रकटीकरण कानूनी रूप से आवश्यक है।

■ INX मीडिया मामला (2019):

- एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इंकार करने के दलिली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय (ED) द्वारा सीलबंद कवर में उपलब्ध कराए गए सबूतों पर आधारित होने के कारण चुनौती दी थी।
 - इस कार्रवाई का आधार नषिपक्ष परीक्षण था।

■ Cdr अमति कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामला (2022):

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक जानकारी का प्रगटीकरण न करना और नरिणायक प्राधकिरण को सीलबंद कवर में इसका प्रगटीकरण करना एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

स्रोत: द हद्रि